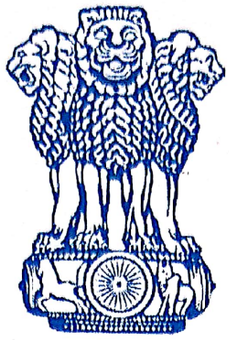


पंजाब के राज्यपाल

# श्री वी.पी. सिंह बदनौर

द्वारा

# विधान सभा

में

दिनांक 1 मार्च, 2021 दिन सोमवार

को दिया गया

# भाषण

माननीय अध्यक्ष और आदरणीय सदस्य साहिबान,

1. मैं 15 वीं पंजाब विधानसभा के 14 वें सत्र के पहले दिन इस अजीम सदन में आपके बीच होने में प्रसन्न्ता महसूस कर रहा हूं। एक साल पहले, हम गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समारोह के दौरान मिले थे। हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया क्योंकि हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड की शताब्दी मनाई थी। मेरी सरकार ने विशाल जनसमूहों वाले इन समारोहों को मनाने के लिए उचित कार्यक्रम आयोजित किए थे। हमने महान सिख जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की 350 वीं जन्म शताब्दी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ श्वेतांबर तेरा पंथ के 10वें प्रमुख की जन्म शताब्दी और भगत नामदेव जी की 750वीं जयंती के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों की योजना बनाई थी, लेकिन वर्ष 2020 एक असामान्य और कठिन वर्ष था।

2. हालांकि, "हिंद की चादर" श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व इस साल 1 मई को मनाया जाएगा। सरकार धर्मनिरपेक्षता की सच्ची भावना को धारण करने वाले महान गुरु साहिब को श्रद्धांजलि देने के लिए श्री आनंदपुर साहिब में एक भव्य समारोह आयोजित करेगी। इसके बाद हम कोविड सावधानियों के साथ पूरे वर्ष के कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे, जो अगले साल गुरपर्व पर समाप्त होगा।

3. आदरणीय सदस्यगण, आप सभी जानते हैं कि कोविड –19 की महामारी और भारत सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के कारण राज्य में एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। कोविड –19 महामारी से

उत्पन्न संकट अज्ञात और अप्रत्याशित था। हालांकि, मेरी सरकार ने इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक लचीलापन और दृढ़ संकल्प दिखाया है। मार्च 2020 में, खतरनाक कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के साथ–साथ कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब देश का पहला राज्य था। मेरी सरकार हमेशा लॉकडाउन लागू करने के साथ–साथ जमीनी परिस्थितियों को बदलने और ढील देने में त्वरित और सक्रिय रही है। परिणामस्वरूप, पंजाब भारत में सबसे कम प्रभावित राज्यों में से एक रहा।

4. हालांकि, आम आदमी बुरी तरह से प्रभावित था, और पूरी तरह से बंद होने से व्यापार, वाणिज्य और उद्योग का सफाया हो गया। मेरी सरकार ने इन कठिन समय में आम लोगों की व्यथा को पहचानते हुए, उनकी आवश्यकताओं, स्वास्थ्य और चिकित्सा मुद्दों, राशन, भोजन और प्रवासी श्रमिकों के परिवहन को पूरा करने के लिए चार समर्पित 24 घंटे के हेल्पलाइन लॉन्च किए। तालाबंदी और कर्फ्यू के दौरान इन हेल्पलाइनों के माध्यम से आम जनता द्वारा प्राप्त 24 लाख से अधिक शिकायतों का प्रभावी ढंग से निपटारा किया गया।

5. मेरी सरकार ने सामाजिक–आर्थिक कठिनाइयों को कम करने और भोजन, दवा, व्यक्तिगत सुरक्षा किट, मास्क और जीवन–रक्षक आपूर्ति जैसे जीवन–रक्षक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करके तनाव को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। मिशन फतेह – कोविड–19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक व्यापक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया था। मेरी सरकार ने सीधे संपर्क और सूचना के लिए त्वरित पहुँच के साथ, कोवा ऐप लॉन्च की, जिसे ई–संजीवनी द्वारा राज्य के 58 लाख से अधिक लोगों और टेली–परामर्श के लिए डाउनलोड किया गया था।

6. वैश्विक और राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की मदद और मार्गदर्शन के साथ, मेरी सरकार ने राज्य में वायरस के प्रसार और जीवन के नुकसान को कम करने के लिए एक टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की रणनीति पर तेजी से काम किया है। जब महामारी फैल गई, तो राज्य के पास कोविड –19 का परीक्षण करने की कोई क्षमता नहीं थी, और नमूने को परीक्षण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे भेजा जाता था। हालांकि, मेरी सरकार मार्च के महीने में पटियाला और फरीदकोट में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में परीक्षण करने में सक्षम थी। प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रति दिन 40 परीक्षणों की प्रारंभिक क्षमता को व्यवस्थित रूप से बढ़ाया गया है, और आज राज्य सात सरकारी प्रयोगशालाओं में 26500 आरटी पीसीआर परीक्षण आयोजित करने में सक्षम है। ऑपरेशन में 46 निजी प्रयोगशालाएँ भी हैं। रैपिड एंटीजन परीक्षणों का उपयोग आवश्यकतानुसार किया गया, लेकिन अधिक विश्वसनीय आरटी–पीसीआर परीक्षणों का उपयोग किया गया। राज्य प्रति दिन 30,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम रहा, और परीक्षण दर हमेशा राष्ट्रीय औसत से अधिक रही।

7. मेरी सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन और विस्तार के लिए तत्काल कदम उठाए और महामारी प्रबंधन और रोकथाम के लिए कोविड केयर सेंटर स्थापित किए। 5238 लेवल–2 ऑक्सीजन एडेड अस्पताल सरकारी सुविधाओं में स्थापित किए गए हैं और 2673 बेड निजी सुविधाओं में प्रदान किए गए हैं। 1530 आईसीयू बेडस की स्थापना की गई, जिसमें 645 वेंटिलेटर–असिस्टेड बेड शामिल हैं। यह सुनिश्चित किया कि बेड की कमी के कारण किसी भी मरीज को उपचार से वंचित न किया जाए।

8. इसके अलावा, राज्य में वर्तमान में 25 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एंबुलेंस और 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एंबुलेंस हैं, जबकि अप्रैल 2020 में केवल 2 एएलएस और 240 बीएलएस एंबुलेंस थीं। राज्य में तीन प्लाज्मा बैंक भी स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने राज्य में कोविड–19 रोगियों के लिए अत्याधुनिक उपचार लाने में मदद की है, जैसे कि उच्च–प्रवाह नाक नलिकाओं का उपयोग।

9. आदरणीय सदस्यगण, इस तरह की महामारी से होने वाली पीड़ा को पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरी सरकार ने इसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी संभव उपाय किए हैं। इसने बेघर, कमजोर और दिहाड़ी मजदूरों को भोजन और आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य आपदा राहत कोष से 90 करोड़ रुपये जारी किए। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने जरूरतमंदों व्यक्तियों की परेशानियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और सरकार ने 29 लाख पैकेट भोजन वितरित किया। राज्य के गैर–सरकारी संगठन, धार्मिक और धर्मार्थ संगठन भी 2 करोड़ सूखे राशन पैकेट वितरित करने के लिए विशेष प्रशंसा के पात्र हैं।

10. मेरी सरकार ने सभी सरपंचों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुखों को ग्राम पंचायत या यूएलबी फंड से भोजन और दवा के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता के साथ, गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को आपातकालीन राहत प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है।

11. गरीबों को राहत देने के लिए, मेरी सरकार ने लगभग 25 लाख वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए 668 करोड़ रुपये की चार

महीने की अग्रिम पेंशन जारी की है। इस अवधि के दौरान, मनरेगा के तहत कार्य को बढ़ाकर 3 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों को ₹115 करोड़ रुपये कमाने में सक्षम बनाया गया। इसके अलावा, तालाबंदी के दौरान 6,000 रुपये प्रति कार्यकर्ता की दर से लगभग 2.9 लाख निर्माण श्रमिकों को 174 करोड़ रुपये से अधिक प्रदान किए गए।

12. इसके अलावा, कोविड –19 के प्रभाव को कम करने के लिए, पीएसपीसीएल ने लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से अपने उपभोक्ताओं को विभिन्न राहतें प्रदान की हैं। इनमें बिजली के बिलों का भुगतान टालना, मौजूदा ऊर्जा बिलों पर एक प्रतिशत की छूट, फिक्स्ड चार्ज में कटौती, विस्तार शुल्क की छूट और बिजली उपभोक्ताओं के लिए गैर–सुरक्षा राशि का संशोधन शामिल है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए मेरी सरकार द्वारा उठाए गए अन्य राहत उपाय थेः 1) ''मीटर रीडिंग ऑन ट्रस्ट'' के तहत पीएसपीसीएल की वेबसाइट पर अपने रीडिंग अपलोड करने के लिए वाणिज्यिक और छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सुविधाय 2) किश्तों में बिजली के बिलों का भुगतानय 3) बिलों का भुगतान न करने के कारण कोई कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, और 4) ए/ए फॉर्म जमा करने की वैधता में वृद्धि।

13. आदरणीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने 375 रेलगाड़ियों में 5 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उनके घरों तक पहुँचाने के लिए 35 करोड़ रुपये का 100 प्रतिशत व्यय किया है। 7,000 विशेष बसों द्वारा 21,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुँचाया गया। सरकार ने राज्य के लोगों को वापस लाने के लिए भी विशेष बसें प्रदान कीं, जो लॉकडाउन के कारण देश

के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए थे, जिनमें नांदेड़ के लगभग 4,000 तीर्थयात्री और कोटा के 2,000 से अधिक छात्र शामिल थे।

14. आदरणीय सदस्यगण, अब तक राज्य में लगभग 1.8 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि देश भर में यह संख्या 1.1 करोड़ से अधिक है। इनमें से करीब 1.7 लाख लोग तंदरुस्त हुए हैं। मुझे पता है कि आप में से भी कुछ इस घातक वायरस से संक्रमित थे। हालांकि, मुझे यह देखकर खुशी हुई कि प्रभावित सदस्य और उनके परिवार पूरी तरह से ठीक हो गए हैं।

15. बेशक महामारी को रोक दिया गया है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना है। मेरी सरकार निकट भविष्य में इस वायरस के पुनः उद्भव को रोकने के लिए उचित परिश्रम और एहतियात बरतना जारी रखेगी। यह राज्य में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना जारी रखेगा।

16. आदरणीय सदस्यगण, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों ने कोविड–19 महामारी को रोकने और प्रबंधित करने के हमारे प्रयासों में एक सराहनीय काम किया है। इस कवायद में हमारे 34 सरकारी कर्मचारियों ने भी हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बहुमूल्य जीवन के नुकसान के बारे में, मैं उनके द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों के लिए, और मेरी सरकार की प्रशंसा और धन्यवाद के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रशंसा व्यक्त करना चाहूंगा।

17. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मेरी सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता थी। इस प्रयास में, मुख्यमंत्री, पंजाब ने 20 अक्टूबर, 2019 को "सरबत सेहत बीमा

योजना" शुरू की, जिसके तहत लगभग 40 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार की दर से स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा, जो राज्य की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या को शामिल करता है। लाभार्थी परिवारों को इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के लिए अब तक 45 लाख व्यक्तिगत ई–कार्ड बनाए गए हैं। ई–कार्ड बनाने के अभियान को तेज करने के लिए एक समर्पित एजेंसी नियुक्त की गई है, जिसे कोविड –19 लॉकडाउन के दौरान रोक दिया गया था। वे लाभार्थी जिनके नाम डेटाबेस में हैं, लेकिन अभी तक ई–कार्ड प्राप्त या डाउनलोड नहीं किए गए हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है। वर्ष के अंत तक, पात्र लाभार्थियों को लगभग 640 करोड़ रुपये की लागत के 5.56 लाख कैशलेस उपचार प्रदान किए गए हैं। इस योजना के तहत, हर दिन औसतन 1500 मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

18. राज्य में स्वास्थ्य क्लीनिक (एचडब्ल्यूसी) स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता को देखते हुए, मेरी सरकार ने अब तक 2046 एच.डब्ल्यू.सी शुरू किए हैं, और 800 और एच.डब्ल्यू.सी जल्द ही लॉन्च किए जाएंगे। कुल मिलाकर, इन केंद्रों ने अब तक राज्य में 71 लाख से अधिक लोगों को ओपीडी सेवाएं प्रदान की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए 400 एच.डब्ल्यू.सी के लिए टेलीमेडिसिन सेवा मार्च 2020 में शुरू की गई थी और अब तक 26,000 से अधिक टेली–परामर्श वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आयोजित किए गए हैं।

19. मेरी सरकार ने राज्य में एस.ए.एस नगर, कपूरथला, होशियारपुर, गुरदासपुर और मालेरकोटला में पांच नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय

लिया है। एस.ए.एस नगर में डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान चालू होगा, जबकि आवश्यक अनुमोदन प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद बाकी मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर देंगे।

20. मेरी सरकार ने भारत सरकार से राज्य में एक क्षेत्रीय वायरोलॉजी संस्थान स्थापित करने और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि मुफ्त में उपलब्ध कराने की अपील की है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है, और वर्तमान में संस्थान के लिए एक जगह खोजने की प्रक्रिया चल रही है।

21. मेरी सरकार ने 16 जनवरी, 2021 को राज्य में कोविड –19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार, 25 फरवरी, 2021 तक 1.22 लाख स्वास्थ्य देखभाल और अन्य फ्रंटलाइन श्रमिकों को टीके की पहली खुराक के रूप में टीका लगाया गया है।

22. मेरी सरकार ने भारत सरकार से राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करने की अपील की है। यदि भारत सरकार इस आवश्यक कर्तव्य को पूरा नहीं करती है, तो मेरी सरकार राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों को अपने संसाधनों के माध्यम से मुफ्त टीकाकरण प्रदान करने के लिए कदम उठाकर अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी।

23. पंजाब के लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के अपने प्रयासों में, मेरी सरकार ने मिशन स्वस्थ पंजाब को पुनर्निर्मित करने का निर्णय

लिया है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्वच्छ हवा, पीने का पानी और अस्वास्थ्यकर भोजन सुनिश्चित करना है। राज्य पर्यावरण विभाग मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 10 उप–मिशनों को लागू करेगा और निगरानी करेगा। ये हैं: स्वस्थ मिट्टी, सुरक्षित भोजन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ग्रीन पंजाब, रोड सेफ्टी, प्ले पंजाब, क्लीन वॉटर, स्वच्छ हवा, कूड़ा प्रबंधन और धान पराली प्रबंधन।

24. हालांकि कोविड–19 वर्तमान में नियंत्रण में है, किसान आंदोलन और किसान समुदाय पर इसके परिणाम आम जनता के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। राज्य के किसानों को लगता है कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए कृषि कानून, अर्थात् (क) किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020, (ख) किसान (सशक्तीकरण और सुरक्षा) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020, और (ग) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 उत्पादकता में वृद्धि के परिणामस्वरूप निश्चित आय पर उनकी चिंताओं को संबोधित नहीं करते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि ये कानून पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित लंबे समय से परीक्षण किए गए कृषि विपणन प्रणालियों को बाधित करेंगे। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) पर खाद्यान्न की खरीद बंद कर देगी।

25. मेरी सरकार ने किसानों की इन चिंताओं को गंभीरता से लिया है। राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ–साथ किसान यूनियनों के साथ विचार–विमर्श के बाद, इस अजीम हाउस ने 28 अगस्त 2020 और 19 अक्टूबर 2020 को दो बार प्रस्ताव पारित किए हैं, भारत सरकार से इन कानूनों को निरस्त करने और मौजूदा एम.एस.पी सिस्टम जारी रखने की अपील की है।

26. केंद्रीय कानूनों के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए, इस प्रतिनिधि सभा ने तीन संशोधित कानून पारित किए, अर्थात् (क) किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (प्रोत्साहन और सरलीकरण) (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक, 2020, (ख) किसान (सशक्तीकरण और सुरक्षा) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक, 2020, और (ग) आवश्यक वस्तुएं (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक, 2020 भी पारित हुआ। ये कानून राष्ट्रपति की सहमति के लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत विचाराधीन हैं।

27. मेरी सरकार को लगता है कि इन तीन केंद्रीय अधिनियमों का अधिनियमित होना सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि यह संविधान की अनुसूची 7 की प्रविष्टि 14 के तहत कृषि राज्य का विषय है। राज्य के मुख्यमंत्री ने बार–बार प्रधान मंत्री से इन कानूनों पर पुनर्विचार करने, किसानों की मांगों को स्वीकार करने और इन नए केंद्रीय कानूनों को वापस लेने की अपील की है।

28. मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, इस सदन ने ''नागरिक प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2020'' के तहत एक और संशोधित कानून भी पारित किया, जिसके तहत 2.5 एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्की मुक्त रखा जाएगा, ताकि किसानों की आजीविका चल सके। यह अधिनियम भी भारत के माननीय राष्ट्रपति की सहमति के लिए विचाराधीन है।

29. आदरणीय सदस्यगण, मेरी सरकार राज्य के किसानों की चिंताओं से पूरी तरह अवगत है क्योंकि वे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हम किसानों और

खेत मजदूरों को कोई कठिनाई नहीं होने देंगे। किसानों को बिजली की मुफ्त आपूर्ति जारी रखने के लिए सरकार स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है।

30. पिछले चार वर्षों में, मेरी सरकार ने पिछले आठ फसल चक्रों में किसानों द्वारा उत्पादित अन्न का एक एक दाना खरीदा है। कुल मिला कर, पिछले चार वर्षों में किसानों को 2.17 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जो कि 2013–14 से 2016–17 के पिछले चार वर्षों के दौरान किसानों को दिए गए भुगतान से लगभग 90,000 करोड़ रुपये अधिक है।

31. वर्ष 2020–21 के दौरान, कोविड–19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, मेरी सरकार ने खाद्यान्न की सुरक्षित, निर्विघन और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित की। खरीद केंद्रों की संख्या 1800 से बढ़ाकर 4000 कर दी गई है, किसानों को ई–पास जारी किए गए हैं, और सभी आवश्यक कोविड–19 सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

32. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न के उचित और समान वितरण के लिए, मेरी सरकार ने राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड आरंभ किए हैं, और अब तक 38.29 लाख पात्र परिवारों को स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए गए हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य में राशन वितरण के लिए अंतर–राज्यीय पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की है, जिससे एनएफएसए लाभार्थी राज्य में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (फेअर प्राईस शाप) से अपने लाभ उठा सकें। उचित मूल्य की दुकानों की संख्या में भी 1004 दुकानों की वृद्धि की गई है।

33. मेरी सरकार ने हाल ही में स्वीकृत राज्य–प्रायोजित स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत लोगों के लाभ के लिए 9.5 लाख लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया

शुरू की है, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन.एफ.एस.ए) के तहत कवर नहीं किया जा सकता था। एन.एफ.एस.ए के तहत 1.47 करोड़ लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

34. अपनी प्रतिबद्धता, और वित्तीय बाधाओं के बावजूद, मेरी सरकार ने 4625 करोड़ रुपये की कुल राहत के साथ 2 लाख से 5.64 लाख तक के छोटे और सीमांत किसानों को ऋण राहत प्रदान की। आगामी वित्तीय वर्ष, अर्थात 2021–22 के दौरान शेष 1.13 लाख पात्र किसानों को मौजूदा ऋण राहत योजना का लाभ प्रदान करने के लिए भी यह प्रतिबद्ध है।

35. मेरी सरकार ने 2019 में पैक्स खेत मजदूरों और भूमिहीन कृषक सदस्यों के लिए ''ऋण राहत योजना'' अधिसूचित की। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 2.5 लाख भूमिहीन मजदूरों को 520 करोड़ रुपये की ऋण राहत प्रदान की जाएगी।

36. मेरी सरकार के मार्गदर्शन में, पंजाब राज्य सहकारी बैंक ने उन कर्जदारों को राहत देने के लिए ऋण निपटान योजना 2020 शुरू की है, जो समय पर अपना बकाया चुकाने में सक्षम नहीं हैं। योजना के तहत, 50,000 से अधिक उधारकर्ता 500 करोड़ रुपये के अपने बकाया का निपटान करने में सक्षम हैं। इसी तरह, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड ने डिफॉल्टरों के लिए ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है, ताकि वे 10,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित करते हुए आसान किस्तों में ऋण चुका सकें।

37. उर्वरकों के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी परीक्षण के बाद

किसानों को 24.30 लाख मिट्टी गुणवत्ता कार्ड वितरित किए गए हैं। गाँव–अनुसार "मिट्टी के नक्शे" तैयार किए गए हैं और राज्य के प्रत्येक गाँव में किसानों को उनकी भूमि की मिट्टी के स्वास्थ्य की पोषण स्थिति से अवगत कराने के लिए तैयार किया गया है।

38. स्थायी कृषि के विकास और किसानों की भलाई के लिए, मेरी सरकार ने केंद्र सरकार की नीति को पूरा करने के लिए अपनी ''किसान उत्पादक संस्थान नीति'' अधिसूचित की है। केंद्र सरकार की ''कृषि अवसंरचना निधि'' योजना को किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

39. कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए, मेरी सरकार ने इंडो–डच कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के तहत जालंधर जिले के गांव धोगरी में एक आलू का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। इसके अलावा अमृतसर जिले के वेरका में एक नाशपाती और पठानकोट जिले के सुजानपुर में एक लीची एस्टेट की स्थापना की जा रही है।

40. पंजाब को आलू बीज हब के रूप में विकसित करने के लिए, पंजाब टिशू कल्चर आधारित बीज आलू अधिनियम, 2020 को गुणवत्तापूर्ण आलू बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। यह एयरोपोनिक्स, नेट हाउस आदि का उपयोग करके आधुनिक टिशू कल्चर तकनीक के माध्यम से आलू के बीज के तेजी से विकसित होने में मदद करेगा।

41. संबद्ध व्यवसायों को विकसित करने के प्रयासों में, मेरी सरकार ने राष्ट्रीय

गोकुल मिशन के तहत एचएफ बैल आयात किए हैं। । वीर्य उत्पादन 24 महीने के भीतर शुरू होने की उम्मीद है और पहले वर्ष के दौरान, लगभग 8000–10,000 वीर्य पाइप का उत्पादन होने की उम्मीद है। नतीजतन, विदेशी जर्मप्लाज्म को स्थानीय जीन पूल में शामिल किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप नस्ल के लिए उच्च स्तर की आनुवंशिक क्षमता होगी।

42. मेरी सरकार तरनतारन जिले के गांव बूह में 20 करोड़ रुपये की कुल लागत से ''क्षेत्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र'' की स्थापना कर रही है। इस का उद्देश्य आनुवंशिक सुधार के माध्यम से भैंसों की नस्लों में सुधार करना और राज्य में भैंसों का एक विशिष्ट झुंड स्थापित करना है।

43. मेरी सरकार ने 32 करोड़ रुपये के निवेश से डब्लिऊ.एच.ओ के दिशानिर्देशों के अनुसार पंजाब पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान (पी.वी.वी.आई), लुधियाना को जी.एम.पी मानकों के अनुसार अपग्रेड कर रही है । इससे राज्य में पशु रोगों की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के टीकों के उत्पादन में सुविधा होगी। पी.वी.वी.आई, लुधियाना ने नई तकनीक के साथ सैल कल्चर क्लासिक स्वाइन फीवर वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया है। इस प्रकार पंजाब इस वैक्सीन का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

44. मेरी सरकार बस्सी पठाना में एक मेगा डेयरी परियोजना भी स्थापित कर रही है। पहले चरण में, 138 करोड़ रुपये की लागत से प्रति दिन 2 लाख लीटर (एल.एल.पी.डी) की क्षमता वाली एसेप्टिक दूध प्रसंस्करण और पैकिंग इकाई स्थापित की जा रही है। इस परियोजना के जून 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। पहले चरण के पूरा होने पर, दूसरे चरण में एसेप्टिक मिल्क

प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता 5 एल.एल.पी.डी होगी।

45. गुरु अंगद देव विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान, लुधियाना में 12.87 करोड़ रुपए की लागत से 25,000 एलएलपीडी की क्षमता और 50,000 एलएलपीडी तक विस्तार योग्य एक फरमेंटिड मिल्क प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग उत्पाद वाला डेयरी उत्पाद नवाचार और उद्यमी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, 13.6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वेरका फिरोजपुर डेयरी में 1 एलएलपीडी की क्षमता वाली एक नई लिक्विड मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग इकाई स्थापित की जा रही है। इन पहलों से राज्य में डेयरी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

46. आदरणीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने मार्च 2017 से अब तक लगभग चार साल पूरे कर लिए हैं। इस अवधि के दौरान, उसने 2017 के चुनावों के दौरान किए गए अपने अधिकांश वादों को पूरा किया है। राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया है, निवेश को प्रोत्साहित किया गया है, कानून और व्यवस्था और सामुदायिक सद्भाव को पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है, नशों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया गया है, राज्य के क्षेत्रीय और जल अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण, विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों और अन्य अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों हेतु प्रयासों को दोगुना कर दिया गया है और निस्संदेह मेरी सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार सृजन और रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

47. मेरी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के परिणामों को हाल ही में संपन्न हुए

नगरपालिका चुनावों में हमारे नागरिकों द्वारा भारी समर्थन और सराहना मिली है। सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 117 यूएलबी में हुए चुनावों में 86 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का बहुमत मिला है। हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक परंपराओं को कायम रखने के लिए शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए राज्य प्रशासन और पंजाब के लोगों की सराहना की जानी चाहिए।

48. 2017–18 में राज्य की जी.डी.पी 4.28 लाख करोड़ रुपये थी जो 2018–19 में बढ़कर 5.22 लाख करोड़ रुपये और 2019–20 में 5.75 लाख करोड़ रुपये हो गई जो 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसी तरह, राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2018–19 में 1,54,313 रुपये से बढ़कर 2019–20 में 1,66,830 रुपये हो गई, जो कि राष्ट्रीय औसत 1,35,050 रुपये से 23.53 प्रतिशत अधिक है।

49. मेरी सरकार ने राज्य में कानून का शासन स्थापित किया है। इसने सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के शांति से रहने के लिए एक आरामदायक वातावरण सुनिश्चित किया है। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और कृषि यानी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के सुरक्षित और आरामदायक वातावरण में पनपने में सक्षम हैं।

50. नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, मेरी सरकार ने तीन–स्तरीय रणनीति अपनाई है। 2017 में सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष कार्य बल राज्य में नशों की आपूर्ति को रोकने में सफल रहा है। इसने ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन ऑफिसर्स (डीएपीओ) प्रोग्राम और बडी प्रोग्राम जैसे व्यापक रूप से प्रशंसित मांग प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से नशों की बढ़ती मांग को प्रभावी रूप से प्रबंधित और नियंत्रित किया है। पिछले चार

वर्षों में 1785 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने के अलावा, मेरी सरकार ने 53,161 ड्रग तस्करों और डीलरों को गिरफ्तार किया है। नशों के दुष्प्रभाव से दस लाख से अधिक लोगों को अवगत कराने के लिए इसने 6.23 लाख ड्रग प्रिवेंशन ऑफिसर्स (डैपो) पंजीकृत किए हैं। इनमें से 1.1 लाख लोग सीधे तौर पर नशे के आदी थे। मेरी सरकार ने लगभग 7.5 लाख बडी ग्रुपों का भी गठन किया है, जिनकी गतिविधियां इस साल महामारी के कारण सीमित रहीं क्योंकि राज्य में शैक्षणिक संस्थान बंद रहे।

51. नशा करने वाले व्यक्तियों के उपचार के लिए, मेरी सरकार ने राज्य में 35 सरकारी और 137 निजी नशामुक्ति केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, 199 सरकारी ओओएटी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं, जिनमें 6.3 लाख से अधिक लोगों ने आऊटडोर उपचार के लिए अपना पंजीकरण कराया है।

52. मेरी सरकार ने राज्य में अवैध शराब की समस्या को रोकने के लिए 2020–21 में ''ऑपरेशन रेड रोज़'' भी शुरू किया। अब तक 1545 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 1.43 लाख लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद की गई है और 12. 3 लाख किलोग्राम कच्ची शराब बरामद और नष्ट की गई है।

53. मेरी सरकार ने नशों और शराब संबंधी अपराधों पर नकेल कसने के अलावा, राज्य में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए अन्य अपराधों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया है। इसने राज्य के विभिन्न आपराधिक गिरोहों के 2687 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। राज्य पुलिस ने 37 आतंकवादी समूहों का भंडाफोड़ किया है और 221 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। सरकार उन सभी धार्मिक ग्रंथों को अपवित्र करने, और धर्म के अनादर की सभी

घटनाओं को न्याय तक ले जाने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रही है, और ऐसे अपराधों के अपराधियों को दंडित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

54. इस अजीम सदन के सदस्यों को पता है कि पहले कभी भी रोजगार सृजन पर इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि मेरी सरकार ने इस महत्वपूर्ण लेकिन उपेक्षित कार्य को दिया है। मार्च 2017 से, 16 लाख से अधिक युवाओं को निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ–साथ स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार खोजने में मदद मिली है। इनमें लगभग 10 लाख युवाओं के लिए स्वरोजगारय निजी क्षेत्र में 5.7 लाख नौकरियांय और सरकार में लगभग 60,000 नौकरियां शामिल हैं। 22 जिला ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पूरी तरह से कार्यशील हैं और युवाओं के लिए उपयुक्त नौकरियों का सृजन पुरजोर ढंग से कर रहे हैं ।

55. मेरी सरकार ने मार्च 2017 से प्रति दिन औसतन 1,100 युवाओं को रोजगार और रोजगार प्रदान किया है। इसके अलावा, मेरी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में मनरेगा के तहत 977 लाख कार्य–दिवस सृजित किए हैं, जो कि 160 लाख कार्य–दिवस बनते हैं, जो कि पिछले शासन के दौरान प्राप्त औसत से 190% अधिक है।

56. परिवहन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को अधिकतम करने और युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, मेरी सरकार ने 7000 नए बस परमिट जारी करने का निर्णय लिया है, जिसमें से 3000 परमिट जारी किए गए हैं, और शेष 4000 परमिट इस वर्ष के दौरान प्रदान किए जाएंगे।

57. युवाओं की संतुष्टि के अनुसार रोजगार सृजन और उपलब्धता तब तक नहीं बढ़ाई जा सकती, जब तक कि राज्य में औद्योगिक निवेश में वृद्धि और तेजी न आए। महामारी ने निश्चित रूप से नए औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की, लेकिन राज्य को अभी भी लगभग 6,300 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ 462 निवेश प्रस्ताव मिले, जो लगभग 43,000 लोगों को संभावित रोजगार प्रदान करेंगे।

58. कुल मिलाकर, मेरी सरकार को अप्रैल 2017 से जनवरी 2021 तक के चार वर्षों में लगभग 2.82 लाख की रोजगार क्षमता के साथ लगभग 71,000 करोड़ रुपये के संभावित निवेश के साथ 1784 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, शिक्षा, पेट्रोकेमिकल, रियल एस्टेट, पर्यटन और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में, और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, स्पेन एवं डेनमार्क जैसे कई देशों और क्षेत्रों से निवेश प्राप्त हुआ है। हाल ही में, पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (इन्वेस्ट पंजाब) को भारत सरकार द्वारा समग्र मापदंड में 100ः अंकों के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाली राज्य निवेश प्रोत्साहन एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई है।

59. उद्योगों के नियमितीकरण के बोझ को कम करने के लिए, पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020 को लागू किया गया था, जिस से उपायुक्त के नेतृत्व में जिला रोजगार और उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक पार्कों में स्थापित नई एमएसएमई इकाइयों को 3 कार्य दिवसों के भीतर और औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित की जा रही इकाइयों को 15 दिनों के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी के

प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया। अब तक पंजाब के विभिन्न जिलों में 19 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को इस अधिनियम के तहत मंजूरी दी गई है।

60. आदरणीय सदस्यगण, आपको यह जानकर खुशी होगी कि एमएसएम इकाइयों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित पायलट प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चुने गए 5 राज्यों में से पंजाब एक था। सरकार इस उद्देश्य के लिए एक व्यापक परियोजना विकसित करने के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार के साथ काम कर रही है।

61. राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार द्वारा कई औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से 383 एकड़ के क्षेत्र को कवर करते हुए लुधियाना जिले के धंनान्सू में एक विश्व स्तरीय आधुनिक साइकिल घाटी विकसित की जा रही है, जो न केवल देश भर से बल्कि विदेशों से भी नए निवेशकों को आकर्षित करेगी। अपनी सहायक इकाइयों के साथ मेसर्स हीरो साइकिल, इस औद्योगिक पार्क के 100 एकड़ में साइकिल और ई–बाइक जैसे परिवहन समाधान बनाने के लिए एक एंकर इकाई स्थापित कर रही है।

62. मेरी सरकार फतेहगढ़ साहिब जिले के वजीराबाद में एक एकीकृत फार्मास्युटिकल पार्क भी स्थापित कर रही है, जो लगभग 130 एकड़ के क्षेत्र को कवर करने वाले फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में है।

63. मेरी सरकार ने 118 करोड़ रुपये के निवेश के साथ लुधियाना के लाडोवाल में 100 एकड़ के क्षेत्र में एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला और एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा यहां एक सामान्य संसाधन के रूप में स्थापित की जा रही है, और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को पूर्व–अनुमोदित प्लाट दिए जा रहे हैं। फूड पार्क में अब तक नौ कंपनियों ने अपना कारोबार स्थापित किया है।

64. मेरी सरकार ने अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारे परियोजना के हिस्से के रूप में एक औद्योगिक निर्माण क्लस्टर के विकास के लिए राजपुरा में 1100 एकड़ से अधिक भूमि भी प्रदान की है।

65. विभिन्न औद्योगिक केंद्र बिंदुओं के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को नियमित रूप से उन्नत किया जा रहा है। मेरी सरकार ने इन स्थानों पर सड़क, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी, सीवरेज आदि जैसे बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर 175 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।

66. उद्योगों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए, 01.03.2020 से 31.08.2020 के मध्य की अवधि को सभी उद्देश्यों और मनोरथों के लिए शून्य अवधि माना जाता है, और इस अवधि के लिए पी.एस.आई.ई.सी द्वारा कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लिया गया है। पी.एस.आई.ई.सी ने महामारी के कारण क्षतिग्रस्त अवधि के लिए किसी भी विस्तार शुल्क के बिना उत्पादन शुरू करने के लिए 6 महीने की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दी है।

67. मेरी सरकार ने पी.एस.आई.डी.सी और पी.एफ.सी के साथ अपने बकाया का

निपटान करने के लिए क्रेडिट कंपनियों के उद्यमियों को प्रोत्साहन और अंतिम अवसर देने के लिए एकमुश्त निपटान नीति को भी अधिसूचित किया है। सरकार ने अपने बॉयलर उपयोगकर्ताओं को नियमित करने के लिए एकमुश्त माफी योजना को अधिसूचित किया है, यदि वे बॉयलर अधिनियम, 1923 और भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना चल रही हैं।

68. मेरी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013–14 तक कर मांगों के लिए वैट और सीएसटी के लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू की है। इस योजना के तहत 49,647 वैट डीलरों को 121.06 करोड़ की राहत दी जाएगी, जिसमें ब्याज और दंड में 100 प्रतिशत तक की राहत होगी।

69. कोविड –19 महामारी की मुश्किलों ने पंजाब में उद्योगों को तकनीकी टैकसटाईल में नए संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है। मेरी सरकार के प्रोत्साहन और सुविधा के साथ, लुधियाना के कपड़ा उद्योग ने कोविड –19 से सुरक्षा के लिए पीपीई बॉडी कवर और एन –95 मास्क बनाना शुरू किया। जीरो बेस से, आज राज्य में 141 अनुमोदित बॉडी कवर पीपीई निर्माता और 16 एन–95 मास्क निर्माता हैं।

70. आदरणीय सदस्यगण, पंजाब उद्यमशीलता और नवाचार का देश है। पंजाबियों की इस सहज क्षमता का लाभ उठाने के लिए, मेरी सरकार ने पंजाब विद्यार्थी योजना शुरू की। इस योजना के तहत, सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पॉलिटेक्निकों जिन के परिसरों में इनक्यूबेटर हैं, को उपस्थिति में 20: की छूट दी जाएगी, और छात्रों को उनके अध्ययन के दौरान उद्यमिता और नवाचार की

प्रवृत्ति के साथ शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में 4ः अनुग्रह अंक दिए जाएंगे।

71. राज्य में प्रारंभिक पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ावा देने के लिए, मेरी सरकार ने अपनी तरह का पहला पंजाब इनोवेशन मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका नेतृत्व निजी क्षेत्र करता है, लेकिन इसे सरकार का समर्थन प्राप्त है। पंजाब इनोवेशन मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रारंभिक चरण में राज्य में निवेश करने के लिए 150 करोड़ रुपये का पंजाब इनोवेशन फंड स्थापित करने का प्रस्ताव है।

72. मेरी सरकार ने एम.एस.एम इकाइयों के लिए एक्सेलेटर प्रोग्राम आरंभ करने के लिए ग्लोबल एलायंस फार मास एंटरप्रूनरशिप के साथ हाथ मिलाया है ताकि उद्यमशीलता की गतिशीलता को सक्षम बनाया जा सके और और एक अनुकूल उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके। लुधियाना में 23 उद्यमियों का पहला समूह एक्सेलेटर प्रोग्राम को सफलतापूर्वक चला रहा है।

73. नामित क्षेत्रों में नवीन उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने वाली आईटी और आईटीई स्टार्ट–अप इकाइयों की सहायता और पोषण करने के लिए, मेरी सरकार ने आईटी मंत्रालय, भारत सरकार, एसटीपीआई, भारतीय व्यापार स्कूल, पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, टीआईई, चंडीगढ़, चंडीगढ़ एंजेल नेटवर्क और अन्य के साथ 21 करोड़ रुपये की लागत से मोहाली में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए भागीदारी की है।

74. आदरणीय सदस्यगण, उद्योग को बिजली सब्सिडी प्रदान करना राज्य में औद्योगिक निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार की कई

पहलकदमियों में से एक है। औद्योगिक और व्यापार विकास नीति, 2017 की अधिसूचना के बाद, सरकार ने उद्योग को 6010 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी प्रदान की है। चूंकि औद्योगिक बिजली की खपत में 23.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसने राज्य में उद्योगों को पुनर्जीवित करने में मदद की है। कुल मिलाकर, राज्य की बिजली मांग में 2016–17 में 44244 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2019–20 में 56769 मिलियन यूनिट, अर्थात 28.30: की वृद्धि हुई है।

75. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) की निवेश को बढ़ावा देने में अहम भूमिका है। व्यवसाय करने में आसानी के लिए, मेरी सरकार ने व्यवसाय प्रक्रिया में सुधार करके एक उद्यमी और नियामक विभागों के बीच भौतिक स्पर्श बिंदुओं को काफी कम कर दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी कई श्रम सुधार इस प्रकार किए गए हैं जिस से श्रमिकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

76. मेरी सरकार ने पंजाब दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जो दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को एक वर्ष में 365 दिनों के लिए 24ग7 खुले रहने की अनुमति देती है। यह न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि अधिक रोजगार भी सृजित करेगा।

77. कारखाना अधिनियम, 1948 में 10 से 20 तक श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए संशोधन किया गया है, जिससे उद्योग जगत को लाभ होगा। कानून में अपराध में कमी को भी शामिल किया गया है। भवन निर्माण योजनाओं को प्रमाणित करने के लिए तकनीकी संस्थानों को अनुमति देने के लिए पंजाब फैक्ट्री नियम, 1952 में संशोधन किया गया है।

78. मेरी सरकार ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत 6 अगस्त, 2020 की एक अधिसूचना के माध्यम से निश्चित अवधि के रोजगार के लिए भी प्रावधान किया है। निश्चित अवधि के अनुबंध के तहत कर्मचारी अपनी सेवा की अवधि के अनुपात में सभी लाभों के हकदार होंगे।

79. मेरी सरकार ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 को लागू करने के लिए 20 श्रमिकों की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 100 कर दिया है। अब से 100 से कम श्रमिकों वाले औद्योगिक संगठनों को उनके स्थायी आदेशों को सत्यापित करने से छूट दी जाएगी।

80. इसके अलावा, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में 100 से 300 श्रमिकों की अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए संशोधन किया गया है। यह बंद होने या छंटनी से पहले पूर्व अनुमति लेने से 300 से कम श्रमिकों वाले उद्योगों को छूट देगा।

81. अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 2020 में अधिनियम की उपयुक्तता के लिए 20 कर्मचारियों की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50 करने के लिए संशोधन किया गया है। यह लाइसेंस पंजीकरण प्राप्त करने के लिए उद्योग के साथ–साथ ठेकेदारों को आवश्यक लचीलापन देगा।

82. मेरी सरकार ने पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 18,500 लाभपात्रियों को 34 करोड़ रुपये का वितरण किया है, और पिछले वर्ष के दौरान पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 6545 लाभार्थियों को 15 करोड़

रुपये दिए गए हैं।

83. जल संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मेरी सरकार ने पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2020 के तहत राज्य जल नियामक प्राधिकरण को सक्रिय किया है। परिणामस्वरूप, भूजल प्राधिकरण द्वारा पहले गहरे और अधिक शोषित ब्लॉकों में कारखाने स्थापित करने के लिए जारी एनओसी को अब राज्य जल नियामक प्राधिकरण द्वारा विचार और जारी किया जाएगा।

84. मेरी सरकार शाहपुर कंडी बांध परियोजना की प्रगति की लगातार निगरानी कर रही है। लगभग 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, और सभी प्रमुख काम दिसंबर 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। परियोजना के सितंबर, 2022 से बिजली उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है।

85. राज्य के माझा क्षेत्र में यूबीडीसी प्रणाली से पानी का उपयोग करने के लिए, मेरी सरकार ने 327 करोड़ रुपये की एक नवीकरण परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें से चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 72 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस परियोजना के 31 मार्च, 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।

86. कंडी क्षेत्र के 6 ब्लॉकों में, 31 मार्च, 2121 तक 3600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए 30 करोड़ रुपये की लागत से 72 नए गहरे ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इस वर्ष 196 करोड़ रुपये की लागत से एसएएस नगर, रोपड़, एस.बी.एस. नगर, होशियारपुर और पठानकोट जिलों के कंडी क्षेत्रों में 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करने हेतु 502 नए गहरे ट्यूबवेल भी लगाए जाएंगे।

87. मेरी सरकार ने व्यक्तिगत खानों की नीलामी की प्रारंभिक प्रक्रिया के बजाय प्रगतिशील बोली के माध्यम से रणनीतिक रूप से स्थापित समूहों में खनन ब्लॉकों के प्रभावी ई–नीलामी को सक्षम करने के लिए राज्य की खनन नीतियों में बड़े बदलाव किए हैं। नीति का उद्देश्य नई तकनीकों का उपयोग करना है, जैसे कि क्यूटी कोड, आरएफआईडी, सीसीटीवी कैमरे और बेहतर प्रबंधन के लिए आईटी एकीकरण। वर्ष 2020–21 के दौरान खनन राजस्व के रूप में 250 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

88. आदरणीय सदस्यगण, अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार, मेरी सरकार ने कैप्टन स्मार्ट कनेक्ट योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों को 1.74 लाख स्मार्ट मोबाइल फोन प्रदान किए हैं। इसने कोविड –19 द्वारा शुरू की गई अनिवार्य ऑनलाइन शिक्षा के संभावित डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद की। मेरी सरकार इस योजना को जारी रखेगी और राज्य के सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी लड़कों एवं लड़कियों को अगले साल यानि 2021–22 में 2 लाख और स्मार्टफोन प्रदान करेगी।

89. मेरी सरकार के फ्लैगशिप लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम 'पढ़ो पंजाब, पढ़ाओ पंजाब' को सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से बारहवीं तक पर्याप्त उम्र और कक्षा स्तर सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध तरीके से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार आने लगा है। प्रथम द्वारा जारी की गई वार्षिक स्थिति की शिक्षा रिपोर्ट (एएसईआर) के अनुसार, पंजाब में छात्रों के प्रशिक्षण स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके

अलावा, वर्ष 2019–20 के लिए 10. 2 वर्ग के 88.36 प्रतिशत का परिणाम 2018–19 में बढ़कर 96.95 प्रतिशत हो गया है, और इन तीन वर्षों के दौरान 28 प्रतिशत से अधिक सुधार हुआ है।

90. मेरी सरकार ने एक स्मार्ट स्कूल नीति को अधिसूचित किया है, और कुल 19,000 सरकारी प्राथमिक, मध्य, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के 9658 को स्मार्ट स्कूलों में परिवर्तित किया है। निर्देश के माध्यम के रूप में अंग्रेजी लगभग 15,000 सरकारी प्राथमिक, मध्य, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 3.72 लाख छात्रों के साथ शुरू की गई है।

91. मेरी सरकार ने डिजिटल शिक्षा पर पूरा जोर दिया है। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए, 16,589 कक्षाओं (54 प्रतिशत) को ई–सामग्री और प्रोजेक्टर और कंप्यूटर जैसे डिजिटल शिक्षण सहायता प्रदान करके स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा छात्रों और स्कूलों को ई–लर्निंग की सुविधा के लिए 3502 टैबलेट प्रदान किए गए हैं।

92. मेरी सरकार द्वारा अपने प्राथमिक विद्यालयों में शुरू की गई प्राथमिक कक्षाओं की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई है। 12,921 स्कूलों में 3.29 लाख से अधिक बच्चे नामांकित हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के अन्य उपायों के साथ, वर्ष 2020–21 तक सरकारी स्कूलों में नामांकन में 14.9: की वृद्धि करने में मदद मिली है।

93. मेरी सरकार ने गुरु नानक देव जी की 550 वीं जयंती के अवसर पर पटियाला में जगत गुरु नानक देव पंजाब राज्य ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना की।

महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, विश्वविद्यालय कार्यशील हो गया है। इसी तरह, पटियाला में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय और गुरु तेग बहादुर स्टेट लॉ विश्वविद्यालय, तरनतारन भी स्थापित किए गए हैं।

94. तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने राज्य में 19 नए आईटीआई स्थापित किए हैं। उद्योग की जरूरतों के लिए प्रशिक्षण को अनुकूलित करने के लिए, दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के तहत लगभग 8500 सीटें बनाई गई हैं। इसके लिए, विभाग ने हीरो साइकिल, ट्राइडेंट लिमिटेड, एवन साइकिल, स्वराज इंजन लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फेडरल मोगुल पटियाला, गोदरेज एंड बॉयस लिमिटेड मोहाली, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड (सोनालिका) जैसे प्रतिष्ठित उद्योगों के साथ भागीदारी की है।

95. इसके अलावा, सरकारी पॉलिटेक्निक और आईटीआई में नामांकन में क्रमशः 2019–20 की तुलना में इस वर्ष 45ः और 60ः की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020–21 के दौरान 37 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे इन केंद्रों की कुल संख्या 322 हो गई है। इन केंद्रों ने वर्ष 2020–21 के दौरान 30,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है।

96. मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय वायु सेना ने 161 एकड़ जमीन पर भारतीय वायु सेना स्टेशन, हलवारा में एक अंतर्राष्ट्रीय सिविल और कार्गो टर्मिनल के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

97. मेरी सरकार ने पटियाला एविएशन कांप्लैक्स (पीएसी) में नागरिक और सैन्य विमानों, विमान इंजन भागों और एवियोनिक भागों के इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल सेटों के लिए स्थापना, रखरखाव और ओवरहाल (एमआरओ) के तकनीकी हब के माध्यम से एक ''सेंटर आफ एक्सीलेंस'' विकसित करने का फैसला किया है। इनके 31 मार्च, 2021 तक शुरू होने की उम्मीद है। पटियाला एविएशन कॉम्प्लेक्स के रनवे को फिर से बनाया गया है और रात की उड़ान को सक्षम बनाने के लिए लाइटें लगाई जा रही हैं।

98. आदरणीय सदस्यगण, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे की माँग भी बहुत व्यापक है, लेकिन महामारी के पिछले वर्ष के दौरान इसमें और वृद्धि हुई है। मेरी सरकार ने अपनी ग्रामीण परिवर्तन रणनीति को स्थानीय संदर्भ बुनियादी ढाँचे को विकसित करने और अधिक स्थानीय नौकरियों के निर्माण पर स्पष्ट ध्यान देकर पुनः परिभाषित किया है। इसने 272 करोड़ रुपये की लागत से 16,843 ग्रामीण बुनियादी ढांचा कार्यों को पूरा करने के लिए स्मार्ट गांव अभियान (एसवीसी) के चरण–1 को पूरा कर लिया है और 2775 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्मार्ट ग्राम अभियान के चरण–2 में प्रवेश किया है। वर्तमान में 13,000 से अधिक गांवों में 48,910 ग्रामीण बुनियादी ढांचा कार्य चल रहे हैं।

99. मेरी सरकार ने अब तक 3278 करोड़ रुपये की लागत से 28,815 किलोमीटर लिंक सड़कों की मरम्मत की है। वर्तमान में, 834 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 6162 किमी सड़कों की मरम्मत की जा रही है, और यह काम 30 जून, 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, ग्रामीण लिंक सड़कों

पर 1000 संकरे पुलों और पुलों को 216 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है और ये कार्य 30.06.2021 तक पूरा हो जाएगा।

100. इसके अलावा, मेरी सरकार ने 2600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा सुविधाओं और ग्रामीण बाजारों को जोड़ने वाली 3362 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है।

101. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत, राज्य ने 15 फरवरी, 2021 तक 1069 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो अब तक की सबसे अधिक राशि है। इसके साथ, 3.20 करोड़ श्रम–दिवस बनाए गए हैं जो 8.39 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान करेंगे।

102. मई 2020 में मानसून के मौसम से पहले, मेरी सरकार ने राज्य भर के सभी गाँव के तालाबों को साफ करने के लिए एक अभियान चलाया और 15,000 से अधिक तालाबों पर काम किया गया। इनमें से 12,300 तालाबों में जल निकासी पूरी हो गई और 7420 तालाबों की गाद निकाल दी गई। इसने न केवल कोविड–19 के प्रभाव में गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि इससे गाँवों में स्वच्छता में भी काफी सुधार हुआ है।

103. इसके अलावा, गाँवों में अपशिष्ट निपटान के मुद्दे को हल करने के लिए तालाबों के पुनर्वास और पुनः तैयारी के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस पहल में 50 करोड़ रुपये की लागत से 190 कार्य शुरू किए गए हैं।

104. मेरी सरकार का मुख्य ध्यान राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर

में सुधार पर है, और इस दिशा में राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों में पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मेरी सरकार ने ''हर घर पानी, हर घर सफाई मिशन'' शुरू किया। पिछले साढ़े तीन वर्षों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के विकास पर 1450 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद, सरकार ने वर्ष 2020–21 में इस उद्देश्य के लिए 1900 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

105. मेरी सरकार ने पहले ही 99.5ः ग्रामीण आबादी को पाइपयुक्त पेयजल आपूर्ति का एक स्रोत प्रदान किया है। अब यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि 31 मार्च, 2022 तक हर ग्रामीण घर तक पीने का पानी पहुंचाया जाए। इसके लिए, 24.86 लाख ग्रामीण परिवारों को पहले ही पाइप जलापूर्ति प्रदान की जा चुकी है, और कोविड–19 के कारण लॉकडाउन के बावजूद इस वर्ष 7 लाख से अधिक कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवारों का कुल कवरेज 71ः है।

106. ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार ने भूजल आधारित जल आपूर्ति योजनाओं के बजाय, विशेष रूप से गुणवत्ता प्रभावित और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में राज्य में सतही जल आधारित पेयजल योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया है।

107. जिला रूपनगर के नूरपुर बेदी ब्लॉक के 39 गाँवों को कवर करने वाली एक सतही जलापूर्ति योजना 2019 में 25 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई थी और जिला मोगा के बाघा पुराना और निहाल सिंह वाला ब्लॉक के 85 गाँवों में एक और बहु–ग्रामीण सतही जल परियोजना हाल ही में 220 करोड़

रुपये की लागत से शुरू की गई है। इसके अलावा जिला पटियाला और फतेहगढ़ साहिब के प्रभावित इलाकों में 3 नए बड़े पैमाने पर बहु स्तरीय ग्रामीण सतह जलापूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके तहत 383 करोड़ रुपये की लागत से 408 गांवों में 95 लाख की आबादी को कवर किया गया है। इस परियोजना के दिसंबर, 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है।

108. मेरी सरकार 60 करोड़ रुपये की लागत से अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर के सीमावर्ती जिलों में 236 आर्सेनिक प्रभावित गांवों में आईआईटी मद्रास के नैनो–सामग्री आर्सेनिक एब्सार्पशन प्रौद्योगिकी पर आधारित 188 आर्सेनिक और आयरन रिमूवल प्लांट (एआईआरपी) स्थापित कर रही है।

109. मेरी सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान 3.9 लाख शौचालयों का निर्माण किया है, जबकि पिछले दस वर्षों के दौरान 1.57 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया था। राज्य अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्त है। कुल मिला कर, मेरी सरकार ने ग्रामीण पंजाब को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए 5.75 लाख ग्रामीण लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए 863 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

110. पंजाब को देश का पहला ऐसा राज्य घोषित किया गया है जिसने 5.77 करोड़ रुपये की लागत से सभी ग्रामीण स्कूलों को पाइप से जलापूर्ति कनेक्शन के साथ कवर किया है। इसी तरह, राज्य के ग्रामीण स्कूलों और आंगनवाड़ियों में लगभग 8500 शौचालयों के निर्माण पर 38 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे सुरक्षित और

स्वस्थ हों और अपने प्रारंभिक वर्षों में अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता की आवश्यकता को पूरा करें।

111. मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2018 में आरंभ की गई महात्मा गांधी सरबत विकास योजना (एमजीएसवीवाई), सबसे अधिक व्यथित और कमजोर आबादी के समावेशी विकास के विलक्षण उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, जिस में यह काफी हद तक सफल रही है। सरबत विकास शिविरों में भाग लेने वाले 11.05 लाख लोगों को अब तक सरकार के विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों के तहत अपेक्षित राहत और लाभ प्राप्त हुए हैं।

112. किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए जो 12 साल या उससे अधिक समय से सरकारी भूमि पर कृषि कर रहे हैं, मेरी सरकार ने ''पंजाब वेलफेयर एंड सेटलमेंट आफ लैंडलेस मार्जनल एंड स्माल आक्युपेंट फार्मरज अलाटमेंट आफ लैंड एक्ट, 2020'' बनाया है। अधिनियम का उद्देश्य न्यूनतम मूल्य के भुगतान पर उक्त अधिभोगियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है।

113. दुर्भाग्यवश, देश में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में पंजाब में सबसे अच्छा भूमि रिकॉर्ड होने के बावजूद, हमारे पास गांवों में 'लाल लकीर' के भीतर स्थित आवासीय मकानों और भूमि के भूमि रिकॉर्ड नहीं हैं। इस प्रकार गांवों के निवासियों के पास अपनी संपत्तियों का कोई स्वामित्व रिकॉर्ड नहीं है, और परिणामस्वरूप, न तो वे मुद्रीकरण करने में सक्षम हैं, और न ही वे इसे अनौपचारिक या गैर–औपचारिक तरीके को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्थानांतरित कर सकते हैं। मेरी सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी स्थायी निवासियों के स्वामित्व अधिकारों की पुष्टि करने और एक नया कानून

बनाकर एक वैधानिक स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, कार्य को समयबद्ध सीमा में पूरा करने के लिए 'मिशन लाल लकीर' शुरू किया जा रहा है।

114. मेरी सरकार शहरी क्षेत्रों के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन – अमरुत मिशन के तहत, मेरी सरकार राज्य के 16 कस्बों में 2785 करोड़ रुपए के प्राजैक्ट चला रही है, जिसमें जालंधर और पटियाला में 24•7 भूतल जलापूर्ति योजनाएं, लुधियाना में बुड्ढा नाला का कायाकल्प, और पटियाला में बड़ी नदी और छोटी नदी शामिल हैं।

115. लुधियाना, अमृतसर, और जालंधर शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और एक विशेष मामले के रूप में, पवित्र शहर सुल्तानपुरलोधी को भी स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। इस मिशन के तहत, मेरी सरकार 1216 करोड़ रुपये की लागत के कार्य कर रही है।

116. आदरणीय सदस्यगण, पंजाब के सभी 163 शहरों और कस्बों को 2 अक्टूबर 2018 को शहरी आवास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। इसके अलावा, इनमें से 84 कस्बों और शहरों को ओडीएफ़ और 48 को ओडीएफ++ शहरों रूप में प्रमाणित किया गया है, जो उच्च स्तर के तीसरे पक्ष के प्रमाणपत्र हैं। शेष 31 कस्बों और शहरों को भी शीघ्र ही ओडीएफ+ /ओडीएफ++ के रूप में प्रमाणित किए जाने की उम्मीद है।

117. मेरी सरकार ने 2018 में जल आपूर्ति, सीवरेज और एसटीपी प्रदान करने के लिए 133 शहरों में एक शहरी मिशन परियोजना शुरू की थी। 2108 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में से 1945 करोड़ रुपये की परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं, और 31.12.2021 तक इन के पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना के तहत, 451 किलोमीटर की जलापूर्ति लाइन, 871 किमी की सीवरेज पाइप और 411 एमएलडी के 26 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

118. मेरी सरकार अमृतसर और लुधियाना में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त नहर आधारित पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को भी लागू कर रही है। इन परियोजनाओं पर लगभग 1928 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

119. पंजाब शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम (पीयूईआईपी) के चरण–1 के तहत, 298 करोड़ रुपए के स्थानीय क्षेत्र विकास कार्य शुरू किए गए थे, जिनमें से 169 करोड़ रुपये की लागत के काम पूरे हो चुके हैं। पीयूईआईपी का दूसरा चरण वर्ष 2021 में शुरू किया गया था, जिसमें 1098 करोड़ रुपए की लागत वाले 4216 कार्य राज्य के 163 यूएलबी में कार्यान्वयन के अधीन हैं।

120. राज्य के कस्बों और शहरों के झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए, मेरी सरकार ने ''पंजाब स्लम डवेलर्स (मालिकाना अधिकार) अधिनियम, 2020'' नामक एक नया कानून बनाया है। अधिनियम का कार्यान्वयन 'बसेरा' नामक एक नई योजना की शुरुआत के साथ शुरू हुआ है और, हमें उम्मीद है कि वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य में रहने वाले एक लाख से अधिक झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना

हक दिया जाएगा।

121. मेरी सरकार ने राज्य में म्यूनिसिपल संपत्तियों का निष्पक्ष और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ''द पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज एक्ट, 2020'' नामक नया कानून बनाया है। यह अधिनियम 12 वर्षों या उससे अधिक समय से नगरपालिका की संपत्तियों के कब्जे में रहने वालों पर मालिकाना हक देने की परिकल्पना भी करता है। इसका उद्देश्य राज्य के नगरपालिका शहरों में छोटे और सीमांत व्यवसायों की आजीविका को सुरक्षित करना है।

122. औद्योगिक और आवासीय सम्पदा के विकास के लिए, मेरी सरकार द्वारा एक नई और अधिक प्रगतिशील भूमि पूलिंग नीति तैयार की गई है। इस नीति के तहत, आवासीय उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाने वाली प्रत्येक 1 एकड़ जमीन के लिए भूमि मालिकों को 1000 वर्गमीटर आवासीय प्लाट और 200 वर्ग गज वाणिज्यिक भूमि की पेशकश की जाएगी। इसी प्रकार, एक औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए 1 एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर भूस्वामियों को, 1100 गज औद्योगिक प्लॉट और 200 गज वाणिज्यिक भूमि दी जाएगी।

123. कोविड –19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, मेरी सरकार ने राज्य में शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि डेवलपर्स और आवंटियों को कई राहतें दी हैं। इनमें नीलामी की गई संपत्तियों, किश्तों के पुनर्निर्धारण और निर्माण की अवधि में विस्तार पर ब्याज की छूट शामिल है। ईडीसी और अन्य शुल्कों के भुगतान में चूक करने वाले डेवलपर्स को एक माफी योजना की पेशकश की गई थी।

124. मेरी सरकार द्वारा बनाई गई राज्य की गरीब और वंचित आबादी के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य से, भारत सरकार गरीब और वंचित समूहों के उद्देश्य से कार्यक्रमों के लिए उदार निधि प्रदान करने में संकोच करती रही है। यह मार्च 2017 में राज्य को देयता हस्तांतरित करके अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को वापस ले लिया गया था। इस प्रकार पंजाब की देयता 60 करोड़ से रुपये से बढ़ कर 800 करोड़ प्रति वर्ष हो गई थी। इसने राज्य की अनुसूचित जाति की 32 प्रतिशत आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और इस प्रभाव को कम करने के लिए, मेरी सरकार ने 'डॉ. बीआर अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' अधिसूचित की थी। हालाँकि, बाद में भारत सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020–21 से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को राज्य के हिस्से को पहले के 10 प्रतिशत (लगभग) के बजाय 40 प्रतिशत पर निर्धारित करके फिर से शुरू किया। मेरी सरकार ने नई योजना को अपनाया है, और भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह 1 अप्रैल 2017 से इसे लागू करे और राज्य को पिछले वर्षों की देयताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करे। वे अभी तक सहमत नहीं हुए हैं। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि योजना के तहत पंजाब का कोई भी योग्य एससी छात्र गैर–रिफंडेबल फीस के किसी भी हिस्से का बोझ नहीं उठाएगा।

125. आशिर्वाद योजना के तहत, जनवरी 2021 तक 1.94 लाख एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को 409 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

126. अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्रों के लाभ के लिए, मेरी सरकार तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए डीबीटी मोड में राज्य में तीन छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रही है – प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजना।

127. अल्पसंख्यक के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, 2020–21 के दौरान डीबीटी के माध्यम से 4.68 लाख छात्रों के बैंक खातों में 76.14 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, डीबीटी मोड के माध्यम से 56 हजार से अधिक छात्रों के बैंक खातों में 30.18 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं, और अल्पसंख्यकों के लिए मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति के तहत 2020–21 के दौरान डीबीटी के माध्यम से 2404 छात्रों के बैंक खातों में 6.45 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।

128. 2017 में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई), और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के बाद, मेरी सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को अधिसूचित करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके अलावा, इसने महिला प्रधान परिवारों के समग्र विकास के लिए 'माता त्रिपता महिला योजना' नामक एक नई योजना भी शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य परिवारों की सहायता के लिए संवेदनशील कमियों की पहचान करना और उस के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना से राज्य में लगभग 8 लाख महिला प्रधान परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है।

129. मेरी सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए 'पंजाब दिव्यांगजन

सशक्तीकरण योजना' (पीडीएसवाई) नामक एक नई योजना भी शुरू की है ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। यहां भी, इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए संवेदनशील कमियों की पहचान करना और उस के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 6.50 लाख विकलांग लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

130. वृद्ध, विधवा, और विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए, मेरी सरकार ने जुलाई 2017 में मासिक पेंशन 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 750 रुपये प्रति माह कर दी थी। इस ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया है कि सभी पात्र व्यक्तियों को हर महीने नियमित रूप से पेंशन दी जाए। 750 रुपये प्रति व्यक्ति की मासिक पेंशन अब नियमित रूप से लगभग 25 लाख लाभार्थियों को बिना किसी व्यवधान या देरी के दी जा रही है। सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 1747 करोड़ रुपये की वार्षिक औसत राशि खर्च की है, जबकि पिछले चार वर्षों के दौरान यह राशि औसतन 633 करोड़ रुपये थी।

131. खेलों को बढ़ावा देने के लिए, मेरी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाया, और राज्यों में खेल के बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस के लिए पर 32 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

132. कोविड–19 महामारी के कारण परिवहन और कनेक्टिविटी में व्यवधानों ने राज्य के विकास में प्रवासी भारतियों की अधिक भागीदारी की मांग पर मेरी सरकार के प्रयासों को बड़ा झटका दिया। इस संबंध में दो बड़ी पहलकदमियां, फ्रेंड्स ऑफ पंजाब ने एनआरआई की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्रामीण

बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य, और कनेक्ट विद युअर रूट्स (सीवाईआर), वर्ष 2020–21 के दौरान लगभग ठप्प रहीं, लेकिन अगले वर्षों के दौरान यह प्रयास दोगुना हो जाएंगे इन कार्यक्रमों को फिर से सक्रिय किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने विभिन्न देशों में 30 मानद समन्वयक नियुक्त किए हैं, जो पंजाबी प्रवासी भारतीयों के मुद्दों को उजागर करते हैं।

133. मेरी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 01–04–2021 से 7500 रुपये प्रति माह से 9400 प्रति माह की दर से बढ़ाने का फैसला किया है। इसने पंजाब सरकार की एजेंसियों द्वारा प्लाटों और घरों के आवंटन में स्वतंत्रता सेनानियों को 2: आरक्षण भी प्रदान किया है। स्वतंत्रता सेनानियों के योग्य उत्तराधिकारियों को राज्य के मैडिकल और तकनीकी कॉलेजों में प्रवेश के लिए 1: का आरक्षण और राज्य सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती के पदों के लिए भी आरक्षण दिया गया है।

134. सरकार के साथ–साथ निजी अस्पतालों में भी एक इनडोर उपचार के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों (स्वयं) के लिए मैडिकल प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। मेरी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी की अविवाहित या बेरोजगार बेटियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं और स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु उपरंत उसकी विधवा के लिए इस सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

135. मेरी सरकार ने 07–12–2020 से रोडवेज या पीआरटीसी बसों में फ्रीडम फाइटर्स और उनके कानूनी वारिसों, अर्थात बेटों, बेटियों, पोतों, पोतियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है।

136. मेरी सरकार ने 15–10–2020 से सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र को दिखाने

पर राज्य के राजमार्गों पर टोल टैक्स से स्वतंत्रता सेनानियों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों (बेटों/बेटियों/पोते/पोतियों) को छूट देने वाली एक अधिसूचना भी जारी की है। ।

137. मेरी सरकार ने 4300 पूर्व सैनिकों को शामिल करते हुए ''गार्डियन्ज आफ गवर्नेंस'' नामक एक योजना शुरू की है, जिसमें उनकी सेवाओं का उपयोग जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है

138. मेरी सरकार ने पंजाब राज्य डाटा नीति, 2020 को अधिसूचित किया है, जो डाटा प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति है। यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी डाटा संरक्षित, सुरक्षित है और डाटा गोपनीयता के सभी मानदंडों का अनुपालन करता है।

139. अगस्त 2020 में, मेरी सरकार एक सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) के लिए एक नीति लाई। इस नीति को लागू करने के लिए स्थापित ऑनलाइन पोर्टल ने नागरिकों को 516 सेवा केंद्रों सहित, कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज कराने और ट्रैक करने का अधिकार दिया है, जो 327 सरकारी सेवाओं की पेशकश करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं।

140. मीडियाकर्मियों की सुरक्षा के लिए, मेरी सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5052 स्क्राइबज को कवर करने का निर्णय लिया। वर्ष 2020 के दौरान राज्य भर में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 4510 पीले पहचान पत्र जारी किए

गए। हम मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन योजना भी लागू कर रहे हैं।

141. पंजाब जेल विकास बोर्ड अधिनियम, 2020 और पंजाब जेल विकास बोर्ड के नियमों को क्रमशः 17.04.2020 और 20.11.2020 को अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत मेरी सरकार ने राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब जेल विकास बोर्ड का गठन किया। यह बोर्ड विभाग को जेल उद्योगों को पुनर्जीवित करने, कैदियों के कल्याण के लिए राजस्व उत्पन्न करने, कैदियों में कौशल विकसित करने और कैदियों के पुनर्वास के लिए नए रास्ते पेश करने में मदद करेगा।

142. मेरी सरकार कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। प्रारंभ में, संसाधनों की कमी के कारण इन को पूरा नहीं किया जा सका और कोविड–19 महामारी ने स्थिति को और प्रतिकूल बना दिया। राज्य सरकार के कर्मचारियों की भूमिका, सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए न केवल उन की लगन और ईमानदारी, बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए अनुशासन और समझ के लिए भी, सराहना योग्य है। सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगी।

143. आदरणीय सदस्यगण, मेरी सरकार की उपलब्धियां वर्ष 2017 में पंजाब के लोगों के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से दर्शाती हैं। इसने निरपक्षता के साथ विकास की नीति अपनाई है और बिना किसी भेदभाव के सभी के सह–अस्तित्व के लिए एक शांतिपूर्ण पंजाब सुनिश्चित किया है। गरीबों के हित में कदम, और सरकार के निर्णय प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट हैं। किसानों को

मुफ्त बिजली (14.23 लाख से अधिक एपी उपभोक्ता), किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को ऋण राहत (5.64 लाख किसान और 2.85 लाख भूमिहीन श्रमिक), घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त और सब्सिडी वाली बिजली (24.31 लाख डीएस उपभोक्ता), सभी को स्वास्थ्य कवर (लगभग 40 लाख परिवार), सामाजिक हिफाजत और सुरक्षा (25 लाख से अधिक व्यक्तियों को पेंशन); 8 लाख महिला प्रधान परिवारों और 6.50 लाख दिव्यांगो को वित्तीय सहायता की विशेष योजनाएँ, और 38.29 लाख स्मार्ट राशन कार्ड वाले 1.47 करोड़ व्यक्तियों को रियायती राशन इस संबंध में सरकार के कुछ सीधे लक्षित कार्य हैं। इन्हें जारी रखा जाएगा, और सरकार पंजाब के लोगों को अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए शेष कार्यों को भी पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। दूसरी ओर, पंजाब के लोग यह सुनिश्चित करने के लिए भी आप सभी से आशा रखते हैं कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हों। मुझे यकीन है कि आप इस अवसर का सदुपयोग करेंगे, और पंजाब को एक मजबूत, समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से कार्य करेंगे। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द !